

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 27-10-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 27 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : International Relations	भारत-आसियान संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है: प्रधानमंत्री
Page 04 Syllabus : GS 2 : Governance and Social Justice / Prelims	‘शून्य नामांकन वाले लगभग 8,000 स्कूलों में 20,000 शिक्षक कार्यरत हैं’
Page 06 Syllabus : GS 2 : International Relations	जापान भारतीय कर्मचारियों की तलाश में है, लेकिन लोगों के बीच संबंध कमज़ोर हैं
Page 08 Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims	हाथ-से-हाथ मिलाकर काम करने का दृष्टिकोण: वैज्ञानिक ही विज्ञान में उत्कृष्टता के सर्वोत्तम निर्णायक हैं
Page 10 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	IUCN ने पश्चिमी घाट पर लाल इंडी क्यों लगाई है?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	भारत-नेपाल आर्थिक संबंधों का समय समाप्त हो रहा है

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी भारत और ASEAN की सदी होगी। कुआलालंपुर में आयोजित 22वें ASEAN-India शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने समुद्री सहयोग, डिजिटल समावेशन, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, ASEAN-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी इंडो-पैसिफिक स्थिरता का एक स्तंभ बन चुकी है, जो मित्रता, विश्वास और पारस्परिक विकास के साझा मूल्यों को दर्शाती है।

India-ASEAN ties making steady progress: PM

He says the current century belongs to India and ASEAN, which represent a quarter of the globe | PM announces further deepening of relations in the domain of maritime security in the year 2026 | Modi promises that India will work for digital inclusion, and also resilient supply chains

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

India-ASEAN strategic partnership has continued to prosper despite the prevailing "era of uncertainties", Prime Minister Narendra Modi said on Sunday.

Delivering his opening remarks virtually at the 22nd ASEAN-India summit being held in the Malaysian capital of Kuala Lumpur, Mr. Modi described ASEAN as a "cultural partner" of India, and announced further deepening of India-ASEAN cooperation in the domain of maritime security in 2026.

"Even in this era of uncertainties, India-ASEAN comprehensive strategic partnership has continued to make steady progress. And this strong partnership of ours is emerging as a robust foundation for global stability and development," the Prime Minister said in his remarks that were telecast to the summit.

'Shared values'

Mr. Modi welcomed Timor-Leste as the newest member of ASEAN, and said India and ASEAN together represented nearly one-fourth of the global population and the two sides were connected by "historical ties and shared values".

"The 21st century is our century, the century of India and ASEAN," he said.

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, who co-chaired the ASEAN-India summit, said India-ASEAN relationship was rooted in the "values of friendship, trust, and shared interests".

"Among the issues and matters discussed were efforts to finalise the ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) and the implementation of the ASEAN-India Plan of Action 2026-2030 to strengthen cooperation in trade, investment, education, food security and technological development," Mr. Ibrahim said.

He appreciated close ties between India and the ASEAN region in the fields of education, economy, and culture.

Mr. Modi said the AITIGA could "unleash the full economic potential" of India-ASEAN relationship.

Humanitarian aid

Mr. Modi said India and the ASEAN member-states in Southeast Asia were "companions in the Global South", and promised that India would work with the ASEAN countries to advance digital inclusion, food security, and resilient supply chains "amid global challenges".

The Prime Minister referred to India's active participation in humanitarian assistance and disaster relief activities in the ASEAN region, and said that to deepen maritime relation between the two sides, 2026 would be declared "ASEAN-India Year of Maritime Cooperation".

Mr. Modi mentioned the danger posed by terrorism and reminded the need for unity in fighting terror. "At the same time, we are steadily advancing our cooperation in education, tourism, science and technology, health, green energy, and cybersecurity," he said, highlighting the "shared cultural heritage" and "people-to-people" ties between India and the ASEAN member-states.

While addressing the heads of governments of the ASEAN region, Mr. Modi conveyed his condolences to the Royal Family and the people of Thailand on the passing of the Queen Mother.

The ASEAN summit began on Sunday with the arrival of heads of the member-countries as well as President Donald Trump of the United States. Ahead of the ASEAN summit, Mr. Modi had called Mr. Ibrahim on October 23 and informed him that he would deliver the speech at the summit virtually.

External Affairs Minister S. Jaishankar is leading the Indian delegation at Kuala Lumpur and he will lead the Indian delegation at the East Asia summit on Monday.

India's relations with the ASEAN member-states had received top level focus since January this year when Indonesian President Prabowo Subianto was hosted here as the guest of honour at the 76th Republic Day celebrations.

Singapore Prime Minister Lawrence Wong visited India in September, and before that, Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. visited India in the first week of August.

Cong. targets PM as Trump repeats oil imports claim

NEW DELHI

Hours after U.S. President Donald Trump reiterated that India will cut down its imports of Russian oil "completely", the Congress criticised Prime Minister Narendra Modi, saying his "hugobolism" was not visible in Kuala Lumpur. » PAGE 4

प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रमुख विश्लेषण

1. ASEAN परिचय:

- ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration) के माध्यम से हुई थी।
- सदस्य देश: ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और टिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) — जिसे 2025 में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।

2. भारत-ASEAN संबंध:

- भारत 1992 में सेक्टरल डायलॉग पार्टनर, 1996 में फुल डायलॉग पार्टनर, और 2012 में रणनीतिक साझेदार (Strategic Partner) बना।
- 2022 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership – CSP) में उन्नत किया गया।
- एक्ट ईस्ट नीति (2014) – संपर्क, संस्कृति और वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने की दिशा में।

- भारत और ASEAN मिलकर दुनिया की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. 2025 शिखर सम्मेलन की प्रमुख घोषणाएँ:

- 2026 को "ASEAN-India Year of Maritime Cooperation" घोषित किया गया।
- समुद्री सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर बल।
- ASEAN-India कार्य योजना (2026-2030) के तहत व्यापार, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक में सहयोग जारी रहेगा।
- ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) को व्यापार क्षमता बढ़ाने हेतु अंतिम रूप देने की दिशा में काम जारी।

4. मानवीय एवं सुरक्षा सहयोग:

- भारत की भागीदारी HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) अभियानों में।
- आतंकवाद के विरुद्ध साझा रुख और साइबर सुरक्षा व हरित ऊर्जा पर बल।

5. 2025 की राजनयिक सक्रियताएँ:

- फिलिपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेस वोंग, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्राएँ — दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय कूटनीति को दर्शाती हैं।
- भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया।

मुख्य परीक्षा हेतु विश्लेषण

1. भारत-ASEAN संबंधों का रणनीतिक महत्व:

- ASEAN इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और Indo-Pacific Oceans Initiative का प्रमुख आधार है।
- यह साझेदारी दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है।
- दोनों पक्ष मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक की साझा दृष्टि रखते हैं।

2. आर्थिक एवं व्यापारिक आयाम:

- ASEAN भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- भारत-ASEAN व्यापार: लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2023-24)।
- AITIGA समीक्षा का उद्देश्य व्यापार को संतुलित बनाना और टैरिफ व गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करना है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और सतत तकनीक में सहयोग की बड़ी संभावनाएँ हैं।

3. समुद्री सहयोग:

- इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा और संपर्क का प्रमुख क्षेत्र।

- भारत की पहलें:
 - Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC–IOR)
 - ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)
 - MILAN नौसैनिक अभ्यास और SAGAR सिद्धांत (Security and Growth for All in the Region)

4. साझा ग्लोबल साउथ एजेंडा:

- भारत और ASEAN ग्लोबल साउथ की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग से वैश्विक मंच पर उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ती है।

5. चुनौतियाँ और आगे की राह:

- व्यापार असंतुलन बना हुआ है — ASEAN की भारत को निर्यात मात्रा अधिक है।
- चीन की बढ़ती भूमिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की भू-राजनीति को जटिल बनाती है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ जैसे भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।
- शिक्षा, पर्यटन, हरित ऊर्जा और AI आधारित नवाचारों में सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता।

निष्कर्ष

- 22वें ASEAN-India शिखर सम्मेलन ने 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पुनः पुष्ट किया। भारत इंडो-पैसिफिक में शांति, समृद्धि और संपर्क को बढ़ाने वाला एक प्रमुख साझेदार बना हुआ है। भारत-ASEAN संबंध भूगोल, संस्कृति और साझा आकांक्षाओं का समन्वय हैं।
- दोनों मिलकर विश्व की एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका सहयोग बहुध्रुवीय, स्थिर और समावेशी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की दिशा में समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी को केंद्र में रखकर साझेदारी को और मज़बूत करना आवश्यक होगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: ASEAN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. ASEAN की स्थापना बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration) के माध्यम से हुई थी।
2. भारत ASEAN का संस्थापक सदस्य है।
3. ASEAN सचिवालय जकार्ता में स्थित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3 **Ans : a)**

UPSC Mains Practice Question

Ques: 21वीं सदी भारत और ASEAN की होगी। इस कथन की विवेचना भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक भू-राजनीति के संदर्भ में करें। (150 Words)

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों के बावजूद — जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और नई शिक्षा नीति (NEP 2020) — अभी भी बुनियादी ढांचे और संसाधनों के उपयोग में गंभीर असंतुलन दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों (2024-25) के अनुसार, देश में करीब 8,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र नामांकित नहीं है, लेकिन 20,000 से अधिक शिक्षक वहाँ कार्यरत हैं। यह स्थिति सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और प्रशासनिक अक्षमता दोनों को उजागर करती है।

'Around 8,000 schools with zero enrolment employ 20,000 teachers'

Press Trust of India
NEW DELHI

Close to 8,000 schools across the country had zero enrolments during the 2024-25 academic session, with West Bengal accounting for most such schools, followed by Telangana, according to official data.

A total of 20,817 teachers were employed in the schools with zero enrolments. In a peculiar case, West Bengal accounted for 17,965 such teachers, along with the highest number of schools without enrolments (3,812).

According to the Ministry of Education's statistics, 7,993 schools had zero enrolments. Meanwhile, Haryana, Maharashtra, Goa, Assam, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Nagaland, Sikkim, and Tripura had no such schools.



A total of 20,817 teachers were employed in the schools with zero enrolments. Bengal accounted for 17,965 such teachers. FILE PHOTO

"School education is a State subject, States have been advised to address the issue of zero enrolments in schools. Some States have merged some schools for optimum utilisation of resources such as infrastructure as well as staff," a senior official said.

There were no schools with zero enrolment in the

Union Territories of Puducherry, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, and Chandigarh, according to the data. Delhi also had no schools with zero enrolments.

The second highest number of such schools was in Telangana (2,245),

followed by Madhya Pradesh (463). While Telangana had 1,016 teachers employed in these schools, Madhya Pradesh employed 223. Uttar Pradesh had 81 such schools.

Over 33 lakh students across the country are enrolled in more than 1 lakh single-teacher schools, with Andhra Pradesh recording the highest number of these schools, followed by Uttar Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, and Lakshadweep. However, when it comes to student enrolment in schools with a single teacher, Uttar Pradesh tops the list, followed by Jharkhand, West Bengal, and Madhya Pradesh.

The number of single-teacher schools decreased from 1,18,190 in 2022-23 to 1,10,971 in 2023-24, recording a drop of around 6%.

मुख्य तथ्य

- कुल बिना नामांकन वाले स्कूल: 7,993
- शिक्षकों की संख्या: 20,817

- राज्यवार स्थिति:
 - पश्चिम बंगाल: 3,812 स्कूल; 17,965 शिक्षक
 - तेलंगाना: 2,245 स्कूल; 1,016 शिक्षक
 - मध्य प्रदेश: 463 स्कूल; 223 शिक्षक
 - उत्तर प्रदेश: 81 स्कूल
- जिन राज्यों में ऐसे कोई स्कूल नहीं: हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।
- जिन केंद्रशासित प्रदेशों में भी नहीं: पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन-दीव, अंडमान-निकोबार, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़।
- एक शिक्षक वाले स्कूल (Single Teacher Schools): पूरे देश में लगभग 1.10 लाख (2023-24)
 - सर्वाधिक संख्या: आंध्र प्रदेश
 - सर्वाधिक छात्र नामांकन: उत्तर प्रदेश
 - 2022-23 की तुलना में 6% की कमी।

Static Context

- संविधानिक स्थिति: शिक्षा (उच्च शिक्षा को छोड़कर) संविधान की राज्य सूची (List II) का विषय है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009: 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है तथा शिक्षक-छात्र अनुपात और स्कूलों की बुनियादी सुविधाएँ तय करता है।
- नई शिक्षा नीति (NEP 2020): शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग और स्कूलों के एकीकरण (Consolidation) पर बल देती है।
- समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha): स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक क्षमता, और ड्रॉपआउट दर को सुधारने का समेकित कार्यक्रम।

विश्लेषण

- प्रशासनिक अक्षमता : बिना छात्रों के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती दिखाती है कि शिक्षा विभागों में डेटा प्रबंधन और संसाधन आवंटन में गंभीर कमी है।
- जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Shift) : कई ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से पलायन और घटती जनसंख्या दर के कारण छात्रों की संख्या में कमी आई है।
- नीति और ज़मीनी अंतर (Policy-Implementation Gap): नई शिक्षा नीति में स्कूलों को जोड़ने (merging) की बात है, लेकिन कई राज्य पुराने ढांचे में ही काम कर रहे हैं।
- वित्तीय बोझ (Fiscal Burden) : ऐसे स्कूलों में शिक्षकों का वेतन और भवन रख-रखाव पर सरकारी पैसा खर्च होता है — जिससे सार्वजनिक निधि (public fund) का दुरुपयोग होता है।
- समानता और गुणवत्ता की चुनौती (Equity and Quality): एक शिक्षक वाले स्कूलों की अधिकता यह दिखाती है कि शिक्षा का समान अवसर देशभर में अब भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है।

सरकारी प्रतिक्रिया (Government Response)

- राज्यों को स्कूलों के एकीकरण (merger) और संसाधनों के इष्टतम उपयोग (optimum utilisation) की सलाह दी गई है।
- UDISE+ (Unified District Information System for Education) के माध्यम से स्कूलों का वास्तविक डेटा ट्रैक करने का प्रयास।
- कई राज्यों ने पहले ही School Mapping और Digital Tracking शुरू किया है।

आगे की राह

- स्कूल एकीकरण: नामांकन रहित या कम नामांकन वाले स्कूलों को आसपास के स्कूलों से जोड़ना चाहिए।
- शिक्षक पुनःतैनाती (Teacher Reallocation): ऐसे शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाए जहाँ शिक्षक कम हैं।
- डिजिटल डेटा ट्रैकिंग: UDISE+ को और मजबूत किया जाए ताकि स्कूल-स्तरीय डेटा पारदर्शी रहे।
- भवनों का पुनःउपयोग: खाली स्कूल भवनों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र या सामुदायिक अध्ययन केंद्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- स्थानीय जागरूकता: नामांकन बढ़ाने के लिए जनजागरण और अभिभावक सहभागिता पर बल दिया जाए।

निष्कर्ष

देश में हजारों ऐसे स्कूलों का होना जिनमें छात्र नहीं हैं, यह दर्शाता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में “पहुंच” (Access) और “उपयोग” (Utilisation) के बीच गंभीर असंतुलन है। नीतियाँ तो हैं, पर कार्यान्वयन (implementation) की कमजोरी ज़मीनी सच्चाई को उजागर करती है। अब ज़रूरत है कि शिक्षा नीति को डेटा आधारित, राज्य विशेष रणनीति के साथ लागू किया जाए ताकि हर शिक्षक के पास छात्र हों — और हर बच्चे को सीखने का अधिकार वास्तविक रूप में मिल सके।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: भारत की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

- स्कूल शिक्षा संविधान की संघ सूची (Union List) का विषय है।
- UDISE+ प्रणाली स्कूल स्तर पर डेटा एकत्र करने का कार्य करती है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है।

सही कथन चुनिए:

- केवल 1
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के कई सरकारी स्कूलों में एक भी छात्र नामांकित नहीं है, जबकि वहाँ शिक्षक कार्यरत हैं। इस स्थिति के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए और शिक्षा व्यवस्था में दक्षता (efficiency) एवं समानता (equity) बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

भारत और जापान के बीच संबंध दशकों से एशिया के सबसे स्थिर और रणनीतिक रिश्तों में गिने जाते हैं। दोनों देशों के बीच सरकार-से-सरकार और व्यापार-से-व्यापार स्तर पर साझेदारी मजबूत हुई है, लेकिन जन-से-जन (people-to-people) संपर्क अब भी बहुत कमजोर है।

वर्तमान स्थिति यह है कि जापान को वृद्ध जनसंख्या की समस्या है और भारत को युवाओं के लिए अवसरों की कमी। ऐसे में दोनों देशों की आवश्यकताएँ एक-दूसरे की पूरक हैं, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की कमी इस साझेदारी की पूरी क्षमता को सीमित कर रही है।

Japan seeks Indian workers but people-to-people ties lag

Japan, with one-third of its population over the age of 65, requires a workforce, academics for research, and a market for its goods, while India, with 65% of its 1.4 billion population under 35, faces rising pressure to create opportunities for its youth

Suhasini Haidar
TOKYO

Since 1981, when Suzuki Motor Corporation set up a factory in India to manufacture the Maruti car, the Japanese company has been a by-word for bilateral ties, Ken-ichi Ayukawa, executive vice-president and chief global marketing officer, who headed Maruti Suzuki operations in India from 2013 to 2022, says.

Suzuki was among the first to bring Japanese engineers to India to streamline processes and train Indian workers to build the car. With both New Delhi and Tokyo seeking solutions to Japan's ageing population and India's burgeoning youth population, the company is now reversing that trend.

"Suzuki is now trying to invite a lot of Indians to Japan, training them and helping them develop technology in Japan," Mr. Ayukawa said, accompanied by Indian scholar and Suzuki executive Chandrali Sarkar. Ms. Sarkar first came to Japan to study at Keio University and has been working on India operations at Suzuki's Hama-



Low numbers: Japan ranks 34th among countries where Indian students pursue higher education. Only about 1,500 Indian students are currently registered in Japan. AFP

matsu headquarters, about 250 km from Tokyo, since 2022. She noted that while some hesitation among Indians stems from limited Japanese language skills, the broader challenge is unfamiliarity with Japan.

"Japan should know more about India and vice versa. Especially the next generation needs to connect, and we need more Indian students, engineers, professionals to come to Japan," said Kenji Hiramatsu, Chairman of the Institute for International Strategy at The Japan Research In-

stitute (JRI), and Japan's Ambassador to India from 2015 to 2019. "It is important that we change the mindset of Indian youth that Japan is a special partner for India," he added, noting that the current number of Indians studying in Japan is far below its potential.

Japan opens doors

According to a parliamentary response from the Indian Ministry of Education last year, Japan ranks 34th among countries where Indian students pursue high-

er education. Only about 1,500 Indian students are currently registered in Japan, a small fraction of more than 3.3 lakh foreign students in the country. Employment figures are similarly modest: about 54,000 Indians work in Japan, one-fourth of the 2.3 lakh Nepali citizens among a total of 23 lakh foreign workers.

To address this shortfall, Japan is preparing to open its doors to thousands like Ms. Sarkar under an "Action Plan" launched by Prime Minister Narendra

Modi and former Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba in August. The plan aims to facilitate five lakh workforce exchanges over the next five years, including the movement of 50,000 skilled personnel from India to Japan.

Officials in the Cabinet Secretariat and the Ministry of Foreign Affairs point to the "perfect complementarity" between the two countries. Japan, with one-third of its population over the age of 65, requires a workforce, academics for research, and a market for its goods. India, with 65% of its 1.4 billion population under 35, faces rising pressure to create opportunities for its youth amid stricter immigration policies in the U.S., Canada, and Europe, and Chinese restrictions on high-tech and semiconductor exports.

Despite decades of growing government-to-government and business-to-business ties, the officials said, people-to-people connections between India and Japan continue to lag.

(The correspondent is visiting Japan at the invitation of the Japanese Ministry of Foreign Affairs)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

सूचकांक	जापान	भारत
65 वर्ष से अधिक जनसंख्या	कुल जनसंख्या का एक-तिहाई	लगभग 7%
35 वर्ष से कम आयु वर्ग	घटता हुआ कार्यबल	65% (1.4 अरब में से)
जापान में भारतीय विद्यार्थी	लगभग 1,500 (जापान 34वें स्थान पर)	बहुत कम
जापान में कार्यरत भारतीय	लगभग 54,000	नेपालियों की संख्या का एक-चौथाई
जापान में कुल विदेशी श्रमिक	लगभग 23 लाख	—

हालिया पहल

भारत-जापान एक्शन प्लान (अगस्त 2024) — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा शुरू किया गया।

मुख्य उद्देश्य:

- 5 वर्षों में 5 लाख कर्मियों का आपसी आदान-प्रदान
- इनमें 50,000 कुशल भारतीय कर्मी जापान जाएंगे
- शैक्षणिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना

पृष्ठभूमि (Static Context)

- भारत-जापान संबंध: 2014 में इसे "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" (Special Strategic and Global Partnership) का दर्जा मिला। फोकस: रक्षा, डिजिटल, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय सहयोग।
- जनांकिकीय पूरकता (Demographic Complementarity):
 - जापान – वृद्ध जनसंख्या, श्रमबल की कमी
 - भारत – युवा जनसंख्या, कौशल उपलब्धता
- मुख्य संस्थागत ढाँचे:
 - Technical Intern Training Program (TITP)
 - Specified Skilled Worker (SSW) Agreement – 2021
 - Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) – 2011
- शिक्षा व संस्कृति:
 - Japan-India Institute for Manufacturing (JIM)
 - Japan-India Skills Transfer Promotion Council बावजूद इसके, छात्र व सांस्कृतिक आदान-प्रदान सीमित है।

विश्लेषण (Analysis)

1. जनांकिकीय आवश्यकता (Demographic Need) : जापान को वृद्ध आबादी के कारण श्रमिकों की कमी है, जबकि भारत के पास विशाल युवा कार्यबल है। लेकिन भाषा, संस्कृति और सामाजिक अंतर के कारण भारतीयों का जापान की ओर झुकाव कम है।
2. जन-से-जन संबंधों की कमजोरी : दोनों देशों में ऐतिहासिक सद्भाव तो है, पर सामाजिक परिचय और सांस्कृतिक संपर्क कमजोर हैं। अधिकांश भारतीय छात्र अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं — जापान अभी भी “अपरिचित विकल्प” है।
3. नीति बनाम वास्तविक जुड़ाव : सरकार और कंपनियों के स्तर पर सहयोग तो मजबूत है (जैसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट), पर आम लोगों के बीच संपर्क और जागरूकता बहुत कम है।
4. वैश्विक अवसरों का नया केंद्र : अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कठोर वीजा नीतियों के बीच, जापान भारतीय युवाओं के लिए एक नया विकल्प बन सकता है — यदि भाषा और वीजा बाधाएँ दूर की जाएँ।
5. धारणा और नीति की खाई (Perception Gap) : जापान का समाज अब भी तुलनात्मक रूप से एकरंगी और बंद माना जाता है, जबकि भारतीय युवाओं को जापान का “तकनीकी लेकिन कठिन” माहौल डराता है।

दोनों देशों के लिए लाभ

जापान के लिए	भारत के लिए
श्रमिकों की कमी पूरी होगी	रोजगार के नए अवसर
कुशल, अंग्रेजीभाषी कर्मी मिलेंगे	कौशल विकास और विदेशी आय
इंडो-पैसिफिक साझेदारी मजबूत होगी	पूर्वी एशिया में सॉफ्ट पावर बढ़ेगी
अनुसंधान और नवाचार को बल	तकनीकी सीख और निवेश प्रवाह

चुनौतियाँ (Challenges)

1. जापानी भाषा की बाधा
2. सख्त वीजा और कार्य संस्कृति
3. सीमित छात्रवृत्तियाँ और शैक्षणिक सहयोग
4. भारतीय डिग्रियों की मान्यता में देरी
5. जापानी समाज में बहुसांस्कृतिक स्वीकार्यता की कमी

आगे का रास्ता (Way Forward)

1. शिक्षा में साझेदारी बढ़ाना: अधिक छात्रवृत्तियाँ, एक्सचेंज प्रोग्राम और IIT-Tokyo University जैसे संयुक्त कार्यक्रम।
2. भाषा प्रशिक्षण: भारत में जापानी भाषा केंद्रों और स्कूल-स्तर पर प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
3. वीज़ा और नीति में सुधार: जापान को अपने वर्क वीज़ा नियम सरल करने चाहिए और भारतीय युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
4. सांस्कृतिक कूटनीति: योग, भारतीय भोजन, सिनेमा और कला के माध्यम से जापान में भारत की सकारात्मक छवि बनाना।
5. कौशल आधारित सहयोग: भारत को जापान की ज़रूरतों के अनुरूप सेक्टर जैसे AI, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, हेल्थकेयर में युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

- भारत और जापान दो ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या संरचना एक-दूसरे की पूरक है — एक ओर वृद्ध समाज, दूसरी ओर युवा समाज। लेकिन यदि लोगों के बीच संपर्क और समझ नहीं बढ़े, तो यह साझेदारी अधूरी रह जाएगी।
- India-Japan Action Plan तभी सफल होगा जब दोनों देश केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े मित्र बनें। सच्ची रणनीतिक गहराई तभी आएगी जब जापानी समाज भारतीयों को अपने विकास का हिस्सा माने, और भारतीय युवा जापान को केवल तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि एक करियर और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में देखें।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

1. Specified Skilled Worker (SSW) समझौता भारतीय पेशेवरों को जापान में काम करने की सुविधा देता है।
2. Japan-India Institute for Manufacturing (JIM) कौशल विकास को बढ़ावा देता है।
3. India-Japan Action Plan (2024) का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग है।

सही कथन चुनिए:

- (a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल (c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

Ans : a)

UPSC Mains Practice Question

Ques. भारत और जापान के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध तो गहरे हैं, लेकिन जन-से-जन संबंध कमजोर बने हुए हैं। इस असंतुलन के कारणों की चर्चा कीजिए और शिक्षा व सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सशक्त करने के उपाय सुझाइए। (150 Words)

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया "राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (Rashtriya Vigyan Puraskar – RVP)" देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। परंतु हाल के विवादों ने इस पहल पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है — क्या यह पुरस्कार वास्तव में वैज्ञानिक उत्कृष्टता का सम्मान है, या इसमें राजनीतिक प्रभाव प्रवेश कर रहा है? संपादकीय का मुख्य तर्क है कि अगर विज्ञान को निष्पक्ष और उत्कृष्ट बनाना है, तो सरकार को 'हैंड्स-ऑफ' यानी गैर-हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और वैज्ञानिकों को ही अपने साथियों के मूल्यांकन का अधिकार देना चाहिए।

पृष्ठभूमि – राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) के बारे में

- स्थापना वर्ष: 2022
- संस्था: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Adviser – PSA) का कार्यालय
- उद्देश्य: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों व टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना।

पुरस्कार की चार श्रेणियाँ

- विज्ञान रत्न (Vigyan Ratna): जीवनभर के योगदान के लिए।
 - विज्ञान श्री (Vigyan Shri): हाल के वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए।
 - विज्ञान युवा – शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार: 45 वर्ष से कम आयु वाले वैज्ञानिकों के लिए।
 - विज्ञान टीम पुरस्कार: तकनीकी विकास में टीम आधारित योगदान के लिए।
- कुल अधिकतम पुरस्कारों की संख्या: 56
 - कोई नकद राशि नहीं, ताकि यह पद्म पुरस्कारों की भावना के अनुरूप रहे।
 - चयन समिति: राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति (Rashtriya Vigyan Puraskar Committee), जिसकी अध्यक्षता PSA करते हैं, और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य शामिल होते हैं।

वर्तमान संदर्भ (Current Context)

- 2025 संस्करण में 24 व्यक्तियों और 1 टीम को पुरस्कार मिला — जो पिछले वर्ष के 33 पुरस्कारों से कम है।
- पुरस्कार घोषणा में कई महीनों की देरी हुई, संभवतः अधिक जाँच के कारण।
- लेकिन इस बीच कई विवाद सामने आए:
 - कुछ वैज्ञानिकों को पहले सूचित किया गया कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा, बाद में नाम हटा दिया गया।
 - प्रमुख वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) को पत्र लिखकर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग की।
 - आरोप लगे कि सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले वैज्ञानिकों के नाम हटाए गए।

Hands-off approach

Scientists are the best judges of excellence in science

The government has announced a list of 24 individual scientists and a team as recipients of the second edition of the Rashtriya Vigyan Puraskar (RVP), awards, conferred by the Centre for scientific achievement. As in 2024, this year too has four broad categories: the Vigyan Ratna, Vigyan Shri, Vigyan Yuva-Shanti Swarup Bhatnagar award and Vigyan team award. The Vigyan Ratna and Vigyan Shri are for scientists who have made distinguished contributions over their lifetime, and recent distinguished contributions respectively. The Yuva is for individuals under 45 and the final one for a team endeavour in technology development.

In theory, the total number of awards, under all categories, is capped at 56; though this year, there are fewer than the 33 awarded last year. The award announcement has been delayed by several months, but this could indicate greater scrutiny of potential awardees. It is important to note that unlike earlier editions of national science awards, for instance the Shanti Swarup Bhatnagar (SSB) awards, there is no cash component given for the RVP, to align with the spirit of the Padma awards. But scrutiny is a double-edged sword. Last year, it emerged that some scientists were told about being recipients, only to be informed later that their names had been dropped. Several prominent scientists across India wrote to the Office of the Principal Scientific Adviser (PSA), demanding transparency in the process of award selection. There were concerns that factors other than scientific merit – for instance, criticism of government policy and political ideology – may have played a role. The PSA has not categorically responded to these demands except to point out that the selection committee, called the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee (chaired by the PSA and which includes Secretaries of Ministries and members of scientific academies), "recommended" awardees to the Minister of Science and Technology. It is not explicit whether the Minister can overturn a recommendation made by the committee. The RVP awards were instituted after the Ministry of Home Affairs and heads of science departments concluded in 2022 that there were too many awards being given out by individual scientific departments and, hence, necessary to trim them and raise their 'stature' to national awards. While awards such as the SSB awards too were finalised in consultation with the Science Minister, the centralisation and the explicit attempt to make the RVP 'Padma-like', means that they appear far more politicised than they ought to be. If the aim of the RVP is to increase 'stature', the government must be seen to have an explicitly hands-off approach and let scientists judge the excellence of their peers.

सांविधानिक व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- पहले विभिन्न वैज्ञानिक विभाग अपने-अपने पुरस्कार देते थे — जैसे:
 - शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (CSIR)
 - INSA पुरस्कार (Indian National Science Academy)
 - DST नवाचार पुरस्कार इत्यादि।
- 2022 में निर्णय हुआ कि सभी को एकीकृत कर राष्ट्रीय स्तर के “विज्ञान पुरस्कार” बनाए जाएँ ताकि “प्रतिष्ठा” बढ़े।
- परंतु इस केन्द्रीयकरण (centralisation) के कारण अब राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा बढ़ गया है।

विश्लेषण (Analysis)

1. स्वायत्तता बनाम केन्द्रीय नियंत्रण

विभिन्न विभागीय पुरस्कारों को मिलाना भले ही प्रशासनिक रूप से आसान हो, लेकिन इससे वैज्ञानिक स्वायत्तता घटती है और निर्णय राजनीतिक प्रभाव के अधीन हो जाते हैं।

2. पारदर्शिता की कमी

यह स्पष्ट नहीं कि

- क्या मंत्री चयन समिति की सिफारिशों को बदल सकते हैं?
- चयन मानक क्या हैं? इस अस्पष्टता से संदेह और असंतोष बढ़ता है।

3. राजनीतिकरण का खतरा

यदि वैज्ञानिकों का सम्मान उनकी राजनीतिक निष्ठा या विचारधारा पर निर्भर लगे, तो यह वैज्ञानिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच को कमजोर कर देता है।

4. वैज्ञानिक समुदाय पर प्रभाव

अनुचित चयन या नाम वापसी से वैज्ञानिक समुदाय में निराशा और अविश्वास फैलता है, और देश की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचती है।

5. वैश्विक तुलना

विश्व स्तर पर जैसे Nobel Prize या Royal Society Fellowships होते हैं — वहाँ चयन केवल वैज्ञानिक साथियों द्वारा किया जाता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता। रत को भी उसी मॉडल को अपनाना चाहिए।

संपादकीय की राय / आगे का मार्ग (Way Forward)

1. सरकार का गैर-हस्तक्षेप (Hands-off Approach): चयन समिति की सिफारिशें अंतिम मानी जाएँ, मंत्री या राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप न हो।

2. पारदर्शी प्रक्रिया: चयन मानदंड, नामांकन प्रक्रिया, समिति की संरचना सार्वजनिक की जाए।
3. वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिकों का मूल्यांकन: चयन पैनल में केवल अनुभवी वैज्ञानिक और अकादमिक विशेषज्ञ हों, नौकरशाह नहीं।
4. राजनीतिक समय-सीमा से स्वतंत्रता: पुरस्कारों की घोषणा राजनीतिक कार्यक्रमों या नीतिगत घोषणाओं से जुड़ी न हो।
5. वैज्ञानिक विश्वास बहाली: यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया जाए कि केवल वैज्ञानिक योग्यता ही चयन का आधार है, न कि विचारधारा या निष्ठा।

निष्कर्ष (Conclusion)

विज्ञान स्वतंत्र सोच, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित होता है। अगर सरकार वास्तव में भारत में वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसे पुरस्कार प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) तभी "राष्ट्रीय गौरव" बन सकता है जब वैज्ञानिक ही वैज्ञानिकों का मूल्यांकन करें, और सरकार केवल संरक्षक की भूमिका निभाए, निर्णायक की नहीं।

एक 'हैंड्स-ऑफ' दृष्टिकोण ही विज्ञान की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता दोनों को मजबूत करेगा।

UPSC Prelims Practice Question

Ques : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) की स्थापना 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी।
2. इसमें चार श्रेणियाँ हैं, जिनमें एक टीम पुरस्कार भी शामिल है।
3. इस पुरस्कार में नकद राशि भी दी जाती है।

सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: विज्ञान में उत्कृष्टता तभी फल-फूल सकती है जब सम्मान प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। इस कथन की विवेचना करते हुए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) के संदर्भ में भारत की नीति और उसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने अपनी World Heritage Outlook 4 (2025) रिपोर्ट में भारत की प्रमुख प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों — पश्चिमी घाट, असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान — को “Significant Concern” (गंभीर चिंता) की श्रेणी में रखा है। यह स्थिति संकेत देती है कि जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों और कमजोर प्रबंधन के कारण इन पारिस्थितिक तंत्रों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है।

यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है — भारत के जैव विविधता वाले क्षेत्र तेज़ी से दबाव में हैं, और Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (2022) के तहत अपने वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।

Why has IUCN red-flagged the Western Ghats?

What has the International Union for Conservation of Nature's World Heritage Outlook 4 report said? What are the four main threats to the loss of habitats and species in South Asia? Are the Western Ghats highly endangered? What are the factors threatening the Sundarbans mangroves?

EXPLAINER

Divya Gandhi

The story so far:

The expansive Western Ghats and two national parks in India — Assam's Manas national park and West Bengal's Sundarbans national park — have been categorised as being of “significant concern” in the International Union for Conservation of Nature's (IUCN) list of natural World Heritage sites across Asia.

Why did the IUCN state?

The IUCN's World Heritage Outlook 4 report released earlier this month attributes four threats to the loss of habitats and species in South Asia: climate change, tourism activities, invasive alien species, and roads. The report categorises the natural sites as “good”, “good with some concerns”, “significant concern”, and “critical”. The report uses four cycles of conservation assessments undertaken since 2014.

“Each of these categories not only shows the potential for a site to preserve its values and underlying attributes but also indicates the urgency of measures that need to be taken to improve the conservation outlook and ensure the long-term conservation of all sites,” says the report. The IUCN assessment of over 200 natural and mixed World Heritage sites “offers the most in-depth analyses of threats facing natural World Heritage around the world and their protection and management status,” says Gretel Aguilar, IUCN director general, in the introduction to the report.

The report points out that the percentage of sites with “a positive conservation outlook has, for the first time, decreased significantly.”

Do we have ‘good’ protected areas?

Protected areas in South Asia are being usurped rapidly, obliterating natural habitats. Of the 228 sites assessed since



Flourishing fauna: A flock of hornbills in the Western Ghats. M. SATHYAMOORTHY

2014, some 63% of sites had a positive outlook in 2014, 2017 and 2020, however, “the IUCN World Heritage Outlook 4 shows that in 2025 only 57% of these sites have a positive conservation outlook.”

The threats are also shapeshifting, “it is ...notable that roads and railroads are now among the top five greatest threats to natural World Heritage in Asia, while in 2020 this was not the case.” The other threats include: forest fires, hunting, roadkill, waste disposal, encroachment, illegal logging etc.

Of the 32 Asian sites categorised as “good with some concerns,” four happen to be in India — The Great Himalayan National Park Conservation Area, Kaziranga National Park, Keoladeo National Park, and Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks. Khangchendzonga National Park in Sikkim has been rated “good” in its

which involves constructing dams across River Sillahalla and River Kundah, with an aim to generate 1,000 MW of power for Tamil Nadu's plains.

Moreover, tourism is creating problems of garbage, often consumed by wild animals such as elephants and exacerbating conflict. Plantations are replacing natural ecosystems. And climate change has forced fauna to adapt by redistributing themselves from fast-warming lower altitudes to higher reaches, such as in the case of the Nilgiri flycatcher and the black and orange flycatcher. Exotic species are colonising natural forests, such as eucalyptus and acacia (both originally from Australia), which were introduced here during the colonial era. As for the Sundarbans mangroves where tigers swim, salinity, heavy metal contamination, and unsustainable resource extraction threatens the ecosystem. Sea level rise and frequent storm surges reduce mangrove biodiversity, says the report.

Is there hope yet?

Outside India, seven sites in China have been proclaimed “best protected and managed protected areas,” including the Badain Jaran Desert-Towers of Sand and Lake, Chengjiang Fossil Site, and Mount Huangshan.

The Natural World Heritage sites make up less than 1% of the Earth's surface, but nurture more than 20% of mapped global species richness. “This includes over 75,000 species of plants, and over 30,000 species of mammals, birds, fishes, reptiles and amphibians,” says the report.

This report is timely. “The world has agreed to halt biodiversity loss through the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, and the UNESCO World Heritage Convention is uniquely placed to meet these challenges by bridging the gap between nature and culture, and protecting places with extraordinary biodiversity, functional habitats and high ecosystem integrity,” says the report.

“This report is more than a health check. It is a guide for action,” says Ms. Aguilar.

THE GIST

▼ The IUCN's World Heritage Outlook 4 report released earlier this month attributes four threats to the loss of habitats and species in South Asia: climate change, tourism activities, invasive alien species, and roads.

▼ The Western Ghats are highly endangered not least by hundreds of hydropower projects.

▼ The Natural World Heritage sites make up less than 1% of the Earth's surface, but nurture more than 20% of mapped global species richness.

रिपोर्ट के बारे में: IUCN World Heritage Outlook 4

जारी करने वाला संगठन: International Union for Conservation of Nature (IUCN) आवृत्ति: हर तीन वर्ष में (2014, 2017, 2020, 2025 — अब तक चार संस्करण)

उद्देश्य: विश्व स्तर पर प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति और प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

मूल्यांकन श्रेणियाँ:

1. Good (अच्छी स्थिति)
2. Good with some concerns (कुछ चिंताओं के साथ अच्छी स्थिति)
3. Significant concern (गंभीर चिंता)
4. Critical (अत्यंत संकटग्रस्त)

भारत की स्थिति (2025 रिपोर्ट में)

श्रेणी	भारतीय स्थल	टिप्पणी
Good	खांचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम)	स्थिति अच्छी और टिकाऊ संरक्षण की संभावना।
Good with some concerns	ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवोलादेव, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स	कुछ दबाव मौजूद, लेकिन नियंत्रित।
Significant concern	पश्चिमी घाट, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिक खतरा गंभीर, त्वरित कदम ज़रूरी।

IUCN द्वारा पहचाने गए चार मुख्य खतरे (दक्षिण एशिया में)

1. जलवायु परिवर्तन – वर्षा, तापमान और समुद्र स्तर में असामान्य बदलाव।
2. पर्यटन का दबाव – अनियंत्रित पर्यटन से कचरा, ध्वनि और आवास हानि।
3. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ – जैसे यूकेलिप्टस, अकाशिया, लैंटाना आदि जो स्थानीय वनस्पति को विस्थापित कर रही हैं।
4. सड़क और बुनियादी ढांचा विस्तार – वनों का विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि।

अन्य खतरे: वनाग्नि, अवैध शिकार, अतिक्रमण, अवैध लकड़ी कटाई, कचरा फेंकना, और जलविद्युत परियोजनाएँ।

केस स्टडी 1: पश्चिमी घाट – "Significant Concern" क्षेत्र

पारिस्थितिक महत्व:

- विश्व के आठ "हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी" में से एक।
- हिमालय से भी पुराना पर्वतीय तंत्र, जिसमें घासभूमि, वन और नदियाँ हैं।
- 325 से अधिक वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास — जैसे नीलगिरी ताहर, लायन-टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल।

मुख्य खतरे:

- जलविद्युत परियोजनाएँ: उदाहरण – ₹5,843 करोड़ की सिल्लहल्ला पंपड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (नीलगिरी)। इससे नदी तंत्र और वन पारिस्थितिकी खतरे में।
- अनियंत्रित पर्यटन: कचरे से जंगली जानवरों को खतरा, जैसे हाथियों द्वारा प्लास्टिक निगलना।
- भूमि उपयोग परिवर्तन: प्राकृतिक वन क्षेत्र चाय, कॉफी और रबर के बागानों में बदल रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन: प्रजातियाँ ऊँचाई की ओर पलायन कर रही हैं (जैसे नीलगिरी फ्लायकैचर, ब्लैक-एंड-ऑरेंज फ्लायकैचर)।
- विदेशी प्रजातियों का आक्रमण: यूकेलिप्टस और अकाशिया जैसी पेड़ प्रजातियाँ देशी पौधों को विस्थापित कर रही हैं।

केस स्टडी 2: सुंदरबन मैंग्रोव्स

पारिस्थितिक भूमिका:

- विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा — रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ और प्रवासी पक्षियों का घर।
- चक्रवात और तूफानों से तटीय रक्षा कवच का काम करता है।

मुख्य खतरे:

- समुद्र-स्तर वृद्धि से लवणता में बढ़ोतरी और ताज़े पानी का प्रवाह घट रहा है।
- औद्योगिक प्रदूषण से भारी धातु जमा हो रहे हैं।
- असतत संसाधन दोहन – अत्यधिक मछली पकड़ना, लकड़ी और केकड़ों का शिकार।
- जलवायु-जनित तूफान और चक्रवात (जैसे अम्फान, बुलबुल) से मैंग्रोव का हास।

स्थैतिक जानकारी: प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों का महत्व

- UNESCO के विश्व धरोहर स्थल वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए घोषित किए जाते हैं।
- ये पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से में फैले हैं, परंतु इनमें विश्व की जैव विविधता का 20% हिस्सा मौजूद है:
 - लगभग 75,000 पौधों की प्रजातियाँ
 - लगभग 30,000 पशु प्रजातियाँ (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ)

भारत के 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल:

1. पश्चिमी घाट
2. सुंदरबन
3. काजीरंगा
4. मानस
5. केवोलादेव
6. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
7. नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स

मुख्य रुझान (2025 रिपोर्ट से)

- सकारात्मक संरक्षण स्थिति वाले स्थलों का प्रतिशत 2014-2020 में 63% था, जो अब 2025 में घटकर 57% रह गया है।
- सड़क और रेल परियोजनाएँ अब शीर्ष पाँच खतरों में शामिल हैं — जो 2020 में नहीं थीं।
- यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने संरक्षित क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला है।

आगे की राह / नीति सुझाव

1. पारिस्थितिकी-आधारित प्रबंधन अपनाएँ – विकास और पर्यटन नीतियों में जैव विविधता संरक्षण को समाहित करें।
2. मजबूत प्रभाव मूल्यांकन (EIA) – परियोजनाओं के सामूहिक पारिस्थितिक प्रभावों को भी आकलित करें।
3. प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा दें – पर्यावरण-संवेदनशील इको-टूरिज़्म को प्रोत्साहन दें।
4. देशी वनस्पतियों का पुनर्वास – विदेशी प्रजातियों को हटाकर देशी पौधों का पुनरोपण करें।
5. जलवायु अनुकूलन योजनाएँ लागू करें – तटीय और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में लचीलापन बढ़ाएँ।
6. स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाएँ – उन्हें संरक्षण का भागीदार बनाकर आजीविका से जोड़ें।

निष्कर्ष

IUCN की यह "रेड फ्लैग" केवल चेतावनी नहीं बल्कि कार्यवाही के लिए मार्गदर्शिका है। भारत को अब प्रतिक्रियात्मक (reactive) संरक्षण से आगे बढ़कर सक्रिय और समग्र (proactive ecosystem management) दृष्टिकोण अपनाना होगा। इन प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की रक्षा केवल वन्यजीवों के लिए नहीं, बल्कि जलवायु स्थिरता, जल सुरक्षा और मानव अस्तित्व की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques : निम्नलिखित में से किन स्थलों को IUCN की World Heritage Outlook 4 (2025) रिपोर्ट में "Significant Concern" श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है?

1. वेस्टर्न घाट 2. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 3. मानस राष्ट्रीय उद्यान 4. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान

सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1 और 4 केवल (b) 1, 2 और 3 केवल (c) 2 और 4 केवल (d) 1, 2, 3 और 4

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत के जैव-विविधता हॉटस्पॉट बढ़ते हुए मानवजनित (anthropogenic) और जलवायुगत (climatic) दबावों के अधीन हैं। IUCN की World Heritage Outlook 4 (2025) रिपोर्ट के निष्कर्षों के संदर्भ में, वेस्टर्न घाट और सुंदरबन के उदाहरणों के साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। (150 Words)

Winding up the clock of India-Nepal economic ties

In October 1, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) Governor Sanjay Malhotra, in the context of internationalising the Indian rupee (INR), announced three measures that have the potential of adding serious positivity in India-Nepal ties.

The first is to allow authorised dealer (AD) banks to lend the INR to non-residents from Nepal, Bhutan and Sri Lanka for cross-border transactions. The second is that the RBI is now going to allow Special Rupee Vostro Accounts, which are accounts of foreign banks with Indian banks in INR, for investment in corporate bonds and commercial papers. This is in addition to the already permitted investments in central government securities. And, the third is to establish a transparent reference rate for currencies of India's major trading partners to facilitate INR-based transactions.

For years, India and Nepal have kept the INR to Nepalese rupee (NPR) exchange pegged at 1.6. There are demands in certain quarters for institutional credit, which are not unfounded as it is this peg that has shielded the NPR from serious depreciation against hard currencies. But it is also worth noting that what is working should not be attempted to be fixed.

The RBI allowing ADs to lend INRs to Nepal should greatly help Nepal in its bilateral trade with India. This is because the Nepalese industry has a lot to gain in overcoming the chronic challenges that it faces for working capital and scalability in the domestic market and in trade with India. Of course, the lending policies of Indian banks and their interest rates would need to be competitive for Nepalese interest.

The hurdles in Nepal

Nepal saw a partial recovery from the COVID-19 induced lockdown based on high remittances but that did not sustain, and its industrial



Manjeev Singh Puri
is India's former Ambassador to Nepal



Atul K. Thakur
is a policy professional, columnist and writer, with a special focus on South Asia

The Reserve Bank of India's moves, especially on Indian rupee lending, can reshape ties

performances continued to be in a tailspin. A key reason was the lack of confidence of Nepalese banks to lend to businesses. Stringent lending considerations by Nepalese banks (mostly controlled by Nepal's big industrial houses) made it even more difficult for small businesses to get the required working capital to sustain and survive. The lack of confidence even made big businesses, with easy access to institutional credit, jittery, with obstacles having crept into their supply chains linked to domestic ancillaries, all of which was compounded by low domestic demand.

These hurdles created structural flaws, leading to economic woes for its population; high unemployment was certainly a big contributing factor in the latest political developments in Nepal.

India's lending outreach should give traction to Nepalese businesses as trade with India should now be devoid of institutional credit hassles. With the United States having announced a tariff of only 10% for Nepal, INR-financed trade with India can lead its imports for value addition in Nepal, build up a global capacity for ancillaries and even explore joint ventures with India.

Trade with India

Indian firms continue to be among the largest investors in Nepal, accounting for 33% of the total foreign direct investment (FDI) stock in Nepal, worth nearly \$670 million. Nepal is India's 17th largest export destination, up from 28 in 2014. India constitutes 65% of Nepalese international trade, including \$8 billion of exports from India to Nepal and just under \$1 billion exports from Nepal to India. India is Nepal's largest export destination, receiving an overwhelming 67% of its total exports consisting of edible oil, coffee, tea and jute.

The uneven, yet interdependent, bilateral

trade fundamentals demand that trade and economic cooperation between India and Nepal should see a further spurt, and for the Nepalese economy, make it less vulnerable and resilient in the topsy-turvy world of today.

Possible multiplier effects

In Nepal, there would be many who would see the RBI moves as an effort to strengthen the INR. But that notwithstanding, Nepal would certainly benefit in lowering the role of the dollar and making INR as preferred currency for trade with India, by far its largest trading partner. It will also shield the economy from the dollar's exchange rate fluctuations. Hard currency availability issues should also ease, thereby reducing pressure on forex and the Current Account Deficit (CAD), which could lead to other advantages and have positive multiplier effects. Indeed, these currency openings should lead to wider consultations between India and Nepal on other crucial economic matters such as Nepal's framework of sovereign guarantees (sector/project wise), Standby Letters of Credit and country risk rating.

Of course, a decoding of the RBI announcements by the Nepal Rastra Bank (NRB) would be useful and important and they may have to put in place several required instrumentalities at their end to take advantage of the Indian move and to protect their economic and money interests. Moreover, the process compliance as per RBI's guidelines will not be something to be skipped by any potential borrowers beyond borders. The RBI has a strong reputation for keeping prudence ahead, and the NRB's reciprocation will herald a new era for rebooting India-Nepal economic ties. India and Nepal should come closer to a level playing field.

The views expressed are personal

GS. Paper 2– International Relations

UPSC Mains Practice Question: Examine the tension between the immunity of international organisations and principles of human rights and natural justice. Illustrate with examples from global judicial practice. (150 Words)

Context :

भारत और नेपाल का संबंध भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक आत्मीयता और आर्थिक परस्पर-निर्भरता पर आधारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर 2025 में किए गए हालिया कदमों ने भारतीय रुपया (INR) के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक नया अध्याय खोला है और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को गहराई देने की संभावना पैदा की है।

RBI द्वारा नेपाल को रुपये में ऋण देने की अनुमति, वॉस्ट्रो खातों के माध्यम से निवेश के नए अवसर, और विदेशी मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दर तय करने जैसे कदम भारत-नेपाल के आर्थिक एकीकरण को नई दिशा दे सकते हैं। यदि इन्हें

सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, तो ये कदम नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ भारत की क्षेत्रीय वित्तीय उपस्थिति को भी सशक्त करेंगे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य : RBI की तीन प्रमुख घोषणाएँ

1. गैर-निवासियों (नेपाल, भूटान, श्रीलंका) को रुपये में ऋण देने की अनुमति भारतीय अधिकृत डीलर (AD) बैंक अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका के गैर-निवासियों को सीमा-पार व्यापार और लेन-देन के लिए भारतीय रुपये में ऋण दे सकेंगे। यह नेपाल की पुरानी तरलता (liquidity) और ऋण से जुड़ी समस्याओं को दूर कर भारत के साथ व्यापार को सुगम बनाएगा।
2. कॉर्पोरेट निवेशों के लिए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते RBI अब विदेशी बैंकों के वॉस्ट्रो खातों (जो भारतीय बैंकों में INR में खोले जाते हैं) को कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स में निवेश की अनुमति देगा। इससे दक्षिण एशिया में रुपये-आधारित निवेश तंत्र और मजबूत होगा।
3. पारदर्शी संदर्भ दर की स्थापना RBI प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के लिए एक पारदर्शी संदर्भ दर तय करेगा, जिससे रुपये में निपटान (settlement) अधिक भरोसेमंद और आकर्षक बनेगा।

पृष्ठभूमि : भारत-नेपाल आर्थिक संबंध

मुद्रा विनिमय अनुपात: 1993 से नेपाली रुपया (NPR) भारतीय रुपये से $1 \text{ INR} = 1.6 \text{ NPR}$ की दर से जुड़ा है। इस स्थिर दर ने नेपाल को मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा अस्थिरता से सुरक्षा दी है।

व्यापार संरचना:

- नेपाल के कुल व्यापार का 65% भारत के साथ है।
- भारत से नेपाल को निर्यात: \$8 अरब
- नेपाल से भारत को निर्यात: \$1 अरब
- नेपाल के मुख्य निर्यात: खाद्य तेल, जूट, कॉफी और चाय

निवेश: भारत नेपाल का सबसे बड़ा निवेशक है — कुल FDI का लगभग 33% (लगभग \$670 मिलियन)। भारतीय कंपनियाँ बैंकिंग, ऊर्जा, विनिर्माण और दूरसंचार क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

विश्लेषण : RBI की नीतियों के आर्थिक प्रभाव

1. नेपाल की तरलता और व्यापार को बढ़ावा INR-ऋण ढांचा नेपाल की उद्योगों को आवश्यक कार्यशील पूंजी और व्यापारिक ऋण प्रदान करेगा, जिससे MSME क्षेत्र और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बल मिलेगा।
2. डॉलर पर निर्भरता में कमी रुपये में व्यापार निपटान से नेपाल की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटेगी —
 - विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा,
 - चालू खाता घाटा (CAD) स्थिर रहेगा,

- डॉलर की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी।
3. क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण को गति : यह कदम दक्षिण एशिया में मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। भूटान और श्रीलंका जैसे देश भी रुपये-आधारित भुगतान तंत्र में शामिल हो सकते हैं। इससे "दक्षिण एशियाई रुपये क्षेत्र (South Asian Rupee Zone)" की नींव पड़ सकती है।
 4. निवेश और औद्योगिक गुणक प्रभाव : अमेरिका द्वारा नेपाल पर मात्र 10% टैरिफ लगाने के बाद, नेपाल भारत से INR में कच्चा माल आयात कर मूल्य-वर्धन कर सकता है और निर्यात को बढ़ा सकता है। इससे संयुक्त उद्योग, विशेष रूप से मैनुफैक्चरिंग और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि होगी।

5. संभावित चुनौतियाँ

चुनौती	प्रभाव
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) की नियामकीय तैयारी	क्रेडिट लाइनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी
बैंकिंग मानकों में अंतर	परिचालन विलंब की संभावना
भारतीय वित्तीय प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता	नेपाल की मौद्रिक संप्रभुता को खतरा
राजनीतिक संवेदनशीलता	नेपाल में आर्थिक निर्भरता पर घरेलू विवाद की संभावना

व्यापक रणनीतिक संदर्भ

- भारत की क्षेत्रीय आर्थिक कूटनीति : RBI की ये पहल भारत की क्षेत्रीय रुपये अंतरराष्ट्रीयकरण नीति का हिस्सा है, जैसे श्रीलंका, मॉरीशस और UAE के साथ हुए समझौते। यह भारत की "Neighbourhood First" और "Act East" नीतियों के अनुरूप है।
- चीन के प्रभाव का संतुलन : चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत नेपाल में बढ़ते निवेश के बीच भारत का यह कदम एक वैकल्पिक, स्थिर और विश्वसनीय मॉडल प्रस्तुत करता है।
- नेपाल की आर्थिक मजबूती: रुपये-आधारित व्यापार और ऋण सुविधा से नेपाल की राजनीतिक रूप से संवेदनशील अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और दक्षिण एशिया में समग्र क्षेत्रीय स्थायित्व बढ़ेगा।

आगे की राह

1. संस्थागत समन्वय: RBI और NRB के बीच संयुक्त "भारत-नेपाल वित्तीय समन्वय तंत्र" (Financial Coordination Mechanism) की स्थापना।
2. नियामक समानता: दोनों देशों के बैंकिंग मानकों, KYC और रिपोर्टिंग नियमों का सामंजस्य।
3. संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा: ऊर्जा, डिजिटल भुगतान और औद्योगिक पार्कों में संयुक्त परियोजनाएँ।
4. क्षमता निर्माण: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) तथा EXIM बैंक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत नेपाली बैंकों को प्रशिक्षित किया जाए।
5. रुपया-नेपाली रुपया विनिमय दर की स्थिरता: 1 INR = 1.6 NPR का स्थिर अनुपात नेपाल की आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष

RBI की अक्टूबर 2025 की घोषणाएँ भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग के इतिहास में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। रुपये में ऋण सुविधा, निवेश के नए मार्ग और मुद्रा पारदर्शिता से भारत ने अपने को नेपाल का सबसे विश्वसनीय आर्थिक साझेदार साबित किया है।

हालाँकि, इन पहलों की सफलता के लिए दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास, नियामक समन्वय और आर्थिक सावधानी आवश्यक है। यदि इन्हें बुद्धिमानी से लागू किया जाए, तो यह सहयोग रुपये-आधारित क्षेत्रीय एकीकरण का आदर्श मॉडल बन सकता है — जो भारत की दृष्टि में एक स्थिर, आत्मनिर्भर और परस्पर जुड़ा हुआ दक्षिण एशिया स्थापित करेगा।